शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 35 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 25 – 1 सितम्बर 2025 मूल्य पांच रूपये

होशियार सिंह की चुनाव याचिका से प्रदेश में राजनीतिक तूफान के संकेत

शिमला/शैल। क्या हिमाचल भी राजनीतिक तूफान की ओर बढ़ रहा है? क्या प्रदेश सरकार संकट में घिर सकती है? यह सवाल पूर्व विधायक और देहरा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे होशियार सिंह द्वारा चुनाव याचिका दायर करने के बाद उठ खड़े हुये हैं। यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी की अगवाई में जिस तरह से वोट अधिकार यात्रा में वोट चोरी के आरोप पर भारी जन समर्थन देखने को मिला है। उससे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार दबाव में आ चुके हैं। क्योंकि इस बार भाजपा का पर्याय बन चुके प्रधानमंत्री मोदी कुछ व्यक्तिगत सवालों में भी बुरी तरह से घिरते जा रहे हैं। यह सवाल खड़े करने वाले भी उन्हीं के विश्वस्त लोग रहे हैं। फिर वोट चोरी का आरोप ऐसे प्रमाणिक आंकड़ों पर आधारित है जिनका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया है। ऐसा माना जा रहा है कि यदि राहुल कि भारत जोड़ो यात्रा भाजपा को लोकसभा में 240 के आंकड़े पर रोक सकती है तो वोट चोरी का आरोप तो और भी बड़ा आरोप है।

ऐसे में इस आरोप का राजनीतिक जवाब देने के लिये कांग्रेस शासित राज्यों में वहां की सरकारों पर हमला बोलकर जवाब देने की रणनीति अपनाई जा सकती है। इसी रणनीति के तहत हिमाचल में ''वोट फॉर कैश'' का मुद्दा अब उठाया जा रहा है। स्मरणीय है कि देहरा विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की ओर से पूर्व विधायक होशियार सिंह उम्मीदवार थे और कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती कमलेश ठाकुर उम्मीदवार थी। इसी उपचुनाव में आचार संहिता लगने के बाद वोटिंग से एक सप्ताह पहले कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक धर्मशाला द्वारा चुनाव क्षेत्र के सारे महिला मण्डलों को पैसा आबंटित किया गया था। कांगड़ा सहकारी बैंक के अतिरिक्त जिला कल्याण अधिकारी द्वारा भी इसी दौरान कुछ महिलाओं को पैसा आबंटित किया गया था। इस पैसा आबंटन को चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन माना गया। प्रदेश विधान सभा के बजट सत्र में हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने इस आश्य का एक सवाल भी पूछा था। जब इसका जवाब नहीं आया तब आशीष शर्मा ने अपनी ओर से जुटाई जानकारी सदन के पटल पर रख दी थी। दूसरी ओर होशियार सिंह ने सूचना के अधिकार के तहत इस संबंध में सारी जानकारी जुटायी और 25 मार्च को महामहिम राज्यपाल को संविधान की धारा 191(1) (e) और 192 के तहत शिकायत भेज दी। लेकिन इस शिकायत पर आज तक कोई कारवाई होना सामने नहीं आया है। बल्कि राज भवन से लेकर पूरी भाजपा तक इस मामले पर खामोश रहे।

अब जब केन्द्र में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा और वोट चोरी के आरोपों के बाद सारा राजनीतिक वातावरण गंभीर हो उठा है तब हिमाचल में इस प्रकरण के इस तरह से पुन: चर्चा में आने को एक अलग ही नजर से देखा जाने लगा है। इस मामले में विधानसभा में पुन: सवाल पूछा गया तो जवाब आया की सूचना एकत्रित की जा रही है। इस पर यह प्रश्न चिन्ह लगा कि जो सूचना आर.टी.आई. के माध्यम से बाहर आ चुकी है उसे सदन में क्यों नहीं रखा जा रहा है। इन्हीं सवालों के बीच होशियार सिंह ने चुनाव याचिका दायर कर मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा दिया है। उच्च न्यायालय में पहुंचने पर स्वभाविक रूप से राजभवन से लेकर पूरी भाजपा में इस पर नये सिरे से हलचल होगी। संविधान और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की जानकारी रखने वालों के मुताबिक इस मामले में राज्यपाल की रिपोर्ट पर ही चुनाव आयोग सारी कारवाई कर सकता है क्योंकि पैसा आबंटन के प्रामाणिक दस्तावेज बाहर आ चुके हैं। इस मामले का प्रदेश की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। सूत्रों की माने तो भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व के संज्ञान में यह मामला आ चुका है और राहुल गांधी को जवाब देने के लिये इसे बड़ा कारगर हथियार माना जा रहा है।

गरीबों की केयर के लिए बनी योजना को बना दिया भ्रष्टाचार की योजना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि हिमकेयर योजना प्रदेश के गरीब और आम आदमी की मदद के लिए शुरू की गई थी, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने इसे अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने की योजना बना दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अब तक इस योजना पर 550 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और किसी भी मरीज का इलाज हिमकेयर योजना की वजह से नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें सुधार किया जाएगा ताकि पात्रों को इसका फायदा मिले।

भाजपा सदस्य विनोद कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल उठाया कि हिमकेयर योजना बंद कर दी गई है और मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने जवाब दिया कि योजना अभी भी चल रही है, लेकिन 364.20 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी बाकी है। उन्होंने बताया कि डायलिसिस के लिए 25 निजी स्वास्थ्य संस्थानों को पंजीकृत किया गया है। हालांकि, निजी अस्पतालों में अनियमितताओं के कारण वहां हिमकेयर की सुविधा कुछ समय के लिए बंद की गई थी।

भाजपा सदस्यों ने आरोप लगाया कि आईजीएमसी, टांडा, नेरचौक, चंबा मेडिकल कॉलेज और एम्स बिलासपुर में हिमकेयर कार्डधारकों को मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष के सदस्य सदन से बाहर चले गये।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्ष की गैरमौजूदगी में कहा कि भाजपा केवल सनसनी फैलाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के समय हिमकेयर का फायदा निजी अस्पतालों और दवा दुकानों ने उठाया। यहां तक कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एमआरआई मशीन न लगाकर निजी अस्पतालों में एमआरआई करवाई जाती रही और हिमकेयर में उसके बिल बनते रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 3,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। चमियाणा अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी शुरू हो चुकी है और जल्द ही टांडा मेडिकल कॉलेज में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। आईजीएमसी, चमियाणा और टांडा अस्पतालों में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड लैब स्थापित की जा रही हैं और इसके लिए 75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हिमकेयर योजना के तहत किसी भी मरीज का इलाज बंद नहीं होगा और सरकार इसमें सुधार करके इसे और प्रभावी बनाएगी।

वर्ष 2023 की तुलना में इस बार हुआ अधिक नुकसान:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने जिला चम्बा के भरमौर, मणिमहेश और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के साथ-साथ कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ प्रभावित फतेहपुर और इंदौरा के मंड क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया।

चम्बा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन जीवन की हानि वर्ष 2023 की तुलना में कम हुई है, लेकिन इस बार विनाश का पैमाना कहीं अधिक है। सड़क, बिजली, पानी आपूर्ति और संचार सेवाएं 2023 की तुलना में अधिक प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित प्रत्येक परिवार के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार विशेष राहत पैकेज प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों को हर संभव राहत पहुंचाने और चंबा भरमौर मार्ग में संपर्क सुविधा बाधित होने के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार सड़क संपर्क बहाल करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसके लिए पोकलेन, जेसीबी और अन्य भारी मशीनरी तैनात की गई है। जिला प्रशासन को यथाशीघ्र सड़क संपर्क बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं, हालांकि खराब मौसम राहत और पुनर्स्थापन कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। भरमौर क्षेत्र में फंसे लोगों की सकुशल वापसी के लिए प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं जो मौसम की अनुकूल परिस्थिति होने पर लोगों को एयरलिफ्ट करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिमहेश यात्रा स्थगित करने का निर्णय मौजूदा मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है, लेकिन कुछ लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। हमें अपनी देव यात्राओं और मणिमहेश

यात्रा पर पूर्ण आस्था है, लेकिन भाजपा नेताओं का इस पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

सुक्खू ने चम्बा के करियां स्थित एनएचपीसी भवन में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने फंसे हुए लोगों के लिए भोजन, पानी, आश्रय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा। साथ ही जिला प्रशासन को क्षतिग्रस्त सड़कों को प्राथमिकता पर खोलने, विशेषकर चम्बा भरमौर एनएच-154ए को बहाल करने और बिजली व पेयजल आपूर्ति योजनाओं को अस्थायी तौर पर बहाल करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कलसुंई क्षेत्र का दौरा भी किया और श्रद्धालुओं से बातचीत की। कलसुंई से श्रद्धालुओं को नूरपुर और पठानकोट भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की गई हैं। शुक्रवार को लगभग 5000 श्रद्धालुओं को कलसुंई से नूरपुर और पठानकोट पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर की ओर से आये श्रद्धालुओं को सलूणी से आगे छोड़ने के लिए छोटे वाहनों की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने सलूणी-खुंडिमरल सड़क को शीघ्र बहाल करने के भी निर्देश दिए ताकि किश्तवाड़ और डोडा जिलों से आए श्रद्धालु अपने घर सुरक्षित लौट सकें। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए एचआरटीसी और निजी संचालकों की अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए अतिरिक्त पानी के कारण चल रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की जानकारी उपायुक्त हेमराज बैरवा से ली।

इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, विधायक नीरज नैयर और सुरेश कुमार, पूर्व मंत्री आशा कुमारी भी उपस्थित थे।

श्रद्धालुओं के लिए निगम ने कलसुंई से पठानकोट तक नि:शुल्क बस सेवा चलाई: उप-मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने भारी बारिश और भूस्खलन के कारण चम्बा ज़िले के कलसुंई क्षेत्र में फंसे श्रद्धालुओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निगम ने कलसुंई से पठानकोट तक नि:शुल्क बस सेवा चलाई है। अब तक 36 बसें यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए लगाई गई हैं और आवश्यकता पड़ने पर अधिक बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। अब तक लगभग 2,250 श्रद्धालुओं को निगम के माध्यम से सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है।

अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यात्रा के दौरान सुगम परिवहन और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने निगम कर्मचारियों की लगन और तत्परता की सराहना की, जिन्होंने सेवा भाव के साथ समय पर फंसे यात्रियों को सहायता प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चम्बा-सलूणी-कोटी पुल सड़क मार्ग बहाल

शिमला/शैल। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने चम्बा और अन्य ज़िलों में भारी बारिश के कारण भू-स्खलन और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में अवगत करवाया गया कि चम्बा से सलूणी और वहां से आगे कोटी पुल तक सड़क बहाल कर दी गई है। सलूणी उप-मंडल के अंतर्गत कोटी पुल से संघणी गांव तक सड़क मार्ग छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। शनिवार तक भारी वाहनों के लिए भी इस सड़क को बहाल कर दिया जाएगा। संघणी से जम्मू-कश्मीर की सीमा से लगते घुंडीमणाल तक सड़क बहाली कार्य युद्ध स्तर पर जारी है।

मुख्य सचिव ने बताया कि इस समय लगभग 1500 लोग चम्बा चौगान में रुके हुए हैं और ज़िला प्रशासन द्वारा उनके लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग भी मदद के लिए सामने आ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि चम्बा प्रशासन द्वारा नूरपुर, कांगड़ा और पठानकोट डिपो से बसें और टैक्सियां भेजने की व्यवस्था की गई हैं ताकि चम्बा की ओर पैदल यात्रा कर रहे लगभग पांच हजार लोगों को उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। उन्हें रास्ते में हर संभव सहायता भी सुनिश्चित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि भरमौर से 25 लोगों को वापस चम्बा लाने के लिए हेलिकॉप्टर द्वारा पांच उड़ाने भरी गई। पर्याप्त खाद्य सामग्री, अधिकारियों और लोक निर्माण विभाग के यांत्रिकी विंग को हवाई मार्ग से भरमौर भेजा गया है।

निदेशक एवं विशेष सचिव आपदा प्रबन्धन डीसी राणा ने बताया कि चुवाड़ी, चम्बा, सलूणी, तीसा और डलहौजी में संचार सेवाएं बहाल करने के प्रयास जारी हैं। ज़िला लाहौल-स्पीति के जिस्पा, दारचा और म्यार में संचार सेवाएं बहाल करने के लिए ईंधन भेज दिया गया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, सचिव लोक निर्माण डॉ. अभिषेक जैन, विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग हरबंस सिंह ब्रसकोन, सचिव सामान्य प्रशासन प्रवीण टाक भी बैठक में उपस्थित थे।

राजस्व तथा बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया क्षतिग्रस्त चंबा-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण

शिमला/शैल। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास तथा जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी ने अपने जिला चंबा के प्रवास के दूसरे

दिन दुनाली से भरमौर तक के क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया तथा इस सड़क मार्ग की शीघ्र बहाली बारे प्रशासन व अन्य विभागीय अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। इससे पूर्व उन्होंने 29 अगस्त को चंबा से बकानी पुल तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का वाहन द्वारा निरीक्षण किया जबकि बकानी पुल से दुनाली तक उन्होंने पैदल यात्रा की। 30 अगस्त को दुनाली से पैदल चलकर जगत सिंह नेगी खड़ा मुख होते हुए भरमौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग का गहन निरीक्षण किया तथा जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने जिला चंबा के एक दिवसीय प्रवास पर आए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी सेटेलाइट फोन के माध्यम से बातचीत की तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 154 ए की क्षति बारे उन्हें विस्तार से अवगत करवाया व इसे बहाल करने वारे अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

अपनी पैदल यात्रा के दौरान जगत सिंह नेगी ने भरमौर से वापस आ रहे श्रद्धालुओं व अन्य लोगों से भी संवाद किया तथा उनसे फीडबैक ली।

भरमौर में मीडिया से बात करते हुए जगत सिंह नेगी ने बताया कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ खड़ी है तथा उन्हें हर संभव मदद मुहैया करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि अगले दो से तीन दिन के भीतर खड़ामुख तथा गैहरा में एचपीएमसी के खरीद केंद्र शुरू कर दिए जाएंगे जहां पर 12 रुपए प्रति किलो की दर से सी ग्रेड का सेब स्थानीय बागवानों से खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 154 की शीघ्र बहाली के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी मशीनरी को पहुंचाने के लिए एयरलिफ्ट बारे विचार किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में कार्यरत जल विद्युत कंपनी जेएसडब्ल्यू द्वारा सड़क बहाली के लिए तुरंत एक पोकलेन उपलब्ध करवाई जा रही है तथा कंपनी के प्रबंधकों द्वारा निकट भविष्य में एक और मशीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

सिविल अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी में स्क्रब टायफस व टायफायड के टेस्ट होंगे नि:शुल्क

शिमला/शैल। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिये सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों

सीएचसी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी में भी स्क्रब टायफस और टायफायड के टेस्ट नि:शुल्क होंगे। इससे पूर्व, यह टेस्ट केवल मेडिकल कॉलेज और जिला स्तरीय अस्पतालों में ही नि:शुल्क होते थे।

इस संबंध में सभी अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की इस पहल से मरीजों को आर्थिक राहत के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त होगी और उन्हें जांच के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा।

बीएमओ करसोग डॉ. गोपाल चौहान ने बताया कि करसोग अस्पताल में भी अब स्क्रब टायफस और टायफायड के टेस्ट पूरी तरह नि:शुल्क किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि करसोग अस्पताल में प्रतिदिन 700 से 800 मरीजों की ओपीडी होती है और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग उपचार के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में स्क्रब टायफस और टायफायड जैसी बीमारियां अधिक सामने आती है। इस नि:शुल्क सुविधा से अब मरीजों को उपचार करवाने में होने वाले खर्च से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व, स्क्रब टायफस और टायफायड की जांच के लिए मरीजों को 196 रुपये तक प्रति टेस्ट देने पड़ते थे।

बीएमओ ने बताया कि सिविल अस्पताल करसोग में ओपीडी में होने वाली भीड़ को नियन्त्रित करने और मरीजों को पारदर्शी एवं समयबद्ध उपचार सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अस्पताल में एक सितंबर, 2025 से टोकन सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस व्यवस्था से मरीजों की जांच क्रमबद्ध और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित होगी तथा भीड़ में होने वाली अव्यवस्था से बचाव होगा।

डॉ. चौहान ने बताया कि अस्पताल में खाली चल रहे विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों को भरने के भी प्रयास किए जा रहे है।

नेरी में छः महीने के भीतर स्थापित होगा बायोचार संयंत्र:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में देश का पहला स्टेट स्पोर्टिड बायोचार कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत हमीरपुर जिला के नेरी में छह महीने के भीतर एक बायोचार संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस संबंध

में ओक ओवर, शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की उपस्थिति में डॉ. वाई एस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, हिमाचल प्रदेश वन विभाग और प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन एमओए हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक उल्लेखनीय कदम है। यह परियोजना जंगल में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने में सहायक सिद्ध होगी, इससे समुदायों के लिए आजीविका के अवसर और जागरूकता भी बढ़ेगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत चीड़ की पत्तियां, लैंटाना, बांस और पेड़-पौधों पर आधारित अन्य सामग्री से पैदा बायोमास का उपयोग करके बायोचार का उत्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर और सोलन ज़िला और चीड़ बहुल क्षेत्रों के लोगों को लाभान्वित करने के लिए समझौता ज्ञापन को छह महीने के भीतर लागू किया जाए। इस पहल से रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य को कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। सतत बायोमास संग्रहण के लिए प्रोक्लाइम, वन विभाग के माध्यम से, स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। लोगों को एकत्रित बायोमास के लिए 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता और मात्रा बनाए रखने के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे।

बायोमास संग्रहण के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 50,000 श्रम दिवस आय उत्पन्न होने की संभावना है। परियोजना से प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे। संरक्षित संग्रहण पद्धतियों, कृषि में बायोचार के उपयोग और जलवायु परिवर्तन पर विश्वविद्यालय की साझेदारी में कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम 10 साल तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान 28,800 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे हिमाचल प्रदेश की हरित पहलों को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत, वनों में लगने वाली आग की घटनाओं पर काबू पाने, लैंटाना के उन्मूलन और पायरोलिसिस तकनीक के माध्यम से बायोचार के उत्पादन के लिए चीड़ की पत्तियों, बांस और अन्य बायोमास अवशेषों का सतत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त प्रारूप तैयार किया गया है। यह पहल मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने, कार्बन पृथक्करण को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कार्बन क्रेडिट और बायोमास संग्रहण एवं कौशल विकास के माध्यम से स्थानीय आजीविका के अवसर पैदा करेगी। प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना के चरणबद्ध कार्यान्वयन में एक मिलियन अमेरिकी डॉलर तक निवेश करेगी।

वन विभाग सामुदायिक भागीदारी के साथ सतत बायोमास संग्रहण का समन्वय और निगरानी, आवश्यक परमिट और रियायतें और वन एवं पर्यावरण नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। विश्वविद्यालय संयंत्र और भंडारण सुविधाओं के लिए नेरी, हमीरपुर में लगभग तीन एकड़ भूमि उपलब्ध करवाएगा। इसके अतिरिक्त, आवश्यक अनुमोदनों के लिए सहयोग और कृषि में बायोचार अनुप्रयोगों पर अनुसंधान करेगा।

वन और कृषि-आधारित बायोमास से प्राप्त बायोचार का उपयोग कृषि, धातु विज्ञान और अन्य उद्योगों में व्यापक रूप से किया जाता है। प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बायोचार उत्पादन, कार्बन क्रेडिट सृजन और जलवायु परिवर्तन शमन परियोजनाओं में विशेषज्ञता से परिपूर्ण कंपनी है। यह कंपनी इस परियोजना की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक पूंजी निवेश करेगी।

इस अवसर पर विधायक सुरेश कुमार, नगर निगम के महापौर सुरेन्द्र चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन संजय सूद, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजेश्वर ठाकुर और कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

चंबा में 394 पेयजल योजनाएं बहाल 100 करोड़ का नुकसान:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राहत एवं बहाली कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिये हैं।

जल शक्ति विभाग को इस आपदा में लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। ज़िले की कुल 487 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिनमें से 394 योजनाओं को आंशिक रूप से बहाल कर दिया गया है। शेष योजनाओं को शीघ्र बहाल करने के लिए तत्परता से कार्य किया जा रहा है।

विशेषकर चंबा-भरमौर क्षेत्र में स्थानीय स्रोतों से अस्थायी जल आपूर्ति व्यवस्था की जा रही है। विभागीय अनुमान के अनुसार इन योजनाओं को पूरी तरह बहाल करने में चार से पांच दिन और लग सकते हैं।

उप-मुख्यमंत्री ने राहत एवं बहाली कार्यों में जुटे कर्मचारियों के साहस और समर्पण की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा के दौरान डयूटी पर तैनात किए गए सभी 41 कर्मचारी सुरक्षित हैं।

अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। जल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

न्यूनतम समय में सड़क मार्गों की बहाली सरकार की उच्च प्राथमिकता:विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। जिला चंबा में 23 से 26 अगस्त तक हुई भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों के निरीक्षण के लिए लोक मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जिला चंबा का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने पठानकोट चंबा राष्ट्रीय

राजमार्ग सहित अन्य विभिन्न संपर्क सड़कों का निरीक्षण भी किया तथा क्षतिग्रस्त स्थलों पर विभागीय अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए।

अपने दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हाल ही में 23 से 26 अगस्त तक पूरे प्रदेश हुई भारी वर्षा के कारण राज्य में भारी क्षति हुई है तथा जिला चंबा भी इसे अछूता नहीं है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समय में सड़क मार्गों की बहाली सरकार की उच्च प्राथमिकता है ताकि आपदा प्रभावित क्षेत्रों मे यातायात सुविधा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग को विभिन्न स्थानों पर हुई क्षति का विस्तृत निरीक्षण किया गया तथा इस संबंध में आवश्यक कारवाई के लिए विभाग के उच्च अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिला के एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग को हुए भारी नुकसान के संबंध में विभागीय अधिकारियों को एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि राष्ट्रीय राजमार्ग की नोडल एजेंसी के माध्यम से यथाशीघ्र बजट की उपलब्धता सुनिश्चित कर समस्या का दीर्घकालिक समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि वे शीघ्र ही क्षतिग्रस्त चंबा-भरमौर राष्ट्रीय राजमार्ग का भी निरीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग यथाशीघ्र बहाल हो। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिला चंबा के ग्रामीण क्षेत्रें में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निर्मित अनेक सड़कों को भी भारी क्षति हुई है जिसके विषय में जिला मुख्यालय चंबा में बैठक आयोजन कर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा ग्रामीण सड़कों के लिए भी सरकार द्वारा विशेष बजट उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्षेत्र वासियों को आवाजाही की समस्या से न जूझना पड़े।

लोक निर्माण मंत्री ने पठानकोट चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा चंबा-खजियार तथा चंबा-साहू मार्ग का भी निरीक्षण उन्होंने परेल घार, मंगला तथा पलयूर में भारी बर्षा से क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का भी निरीक्षण किया।

इस अवसर पर स्थानीय विधायक नीरज नैयर, पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता विकास सूद व अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार सहित लोक निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

महाविद्यालयों व विद्यालयों में अगले सत्र से बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में किया जाएगा आरम्भः शिक्षा मंत्री

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय एमएसडीई और हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रदेश के विद्यालयों और

महाविद्यालयों में अगले शैक्षणिक सत्र से बागवानी को व्यावसायिक विषय के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया गया।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बागवानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो सेब, आम, नींबू प्रजाति के फलों और अन्य फलोत्पादन के माध्यम से प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। कक्षा 9वीं से 12वीं और आगे स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर बागवानी विषय को शामिल करने से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और उद्यमशीलता की भावना विकसित होगी। इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के साथ-साथ फल उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और संबध उद्योगों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

रोहित ठाकुर ने शिक्षा विभाग को मंत्रालय द्वारा मांगी गई सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए ताकि यह पाठयक्रम अगले शैक्षणिक सत्र से लागू हो सके। उन्होंने कहा कि विद्यालय स्तर पर ही बागवानी की पढ़ाई शुरू करने से बच्चों में खेती, पर्यावरण संतुलन और राज्य की समृद्ध कृषि परंपराओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित होगी। हिमाचल की लगभग 90 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ऐसे में बच्चों को बागवानी को सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि एक आधुनिक, लाभकारी और सम्मानजनक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश हमेशा आग्रणी रहा है, जिसका प्रमाण असर, परख और एनएएस सर्वेक्षणों के सकारात्मक परिणामों में दिखे हैं। अब प्रदेश को कौशल आधारित शिक्षा की दिशा में भी मजबूती से आगे बढ़ने के लिए भी समान प्रतिबद्धता दिखानी होगी। बागवानी का समावेश कक्षा की पढ़ाई और व्यवहारिक कार्यानुभव के बीच की दूरी कम कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगा।

उन्होंने कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय से आग्रह किया कि पाठयक्रम हिमाचल की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार तैयार किया जाए। उन्होंने शिक्षकों को कृत्रिम मेधा एआई का प्रशिक्षण देने पर भी बल दिया, ताकि वे आधुनिक तकनीकों को शिक्षा में प्रभावी ढंग से शामिल कर सकें।

राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद एनसीवीईटी की कार्यकारी सदस्य नीना पाहुजा ने प्रदेश को मंत्रालय की ओर से हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि एनसीवीईटी हिमाचल के लिए उपयुक्त मॉडयूल तैयार करने में मदद करेगा। इस अवसर पर एनसीवीईटी ने एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी।

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा अभियान और स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने सुझाव साझा किए।

समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा और पाठयक्रम शुरू करने के लिए कार्य योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

मल्टी-स्पेशियलिटी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की

शिमला/शैल। मैक्स अस्पताल, मोहाली ने देवभूमि अदवेता अस्पताल, ऊना के साथ साझेदारी में अपनी मल्टी-स्पेशियलिटी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की। यह सुविधा मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी और न्यूरोलॉजी सहित स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर एक्सपर्ट सलाह प्रदान करेगी।

मैक्स से सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी डॉ. राहुल महाजन हर महीने के दूसरे मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 2.30 बजे तक, प्रिंसिपल कंसलटेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डॉ. मुकेश कुमार राठौर हर रविवार को सुबह 11.30 बजे से 2.30 बजे तक और, एसोसिएट कंसल्टेंट पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी डॉ. कृतिका गोयल हर महीने के दूसरे मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 2.30 बजे तक ओपीडी में कंसल्टेशन के लिये उपलब्ध होगी ।

मैक्स अस्पताल पेशेंट-सेन्ट्रीक देखभाल प्रदान करने, अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने और पेशेंट की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित है। ऊना में ओपीडी सेवाओं की शुरुआत मैक्स अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को बढ़ाने और सामुदायिक सेवाओं में उत्कृष्टता प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

विविधता में एकता प्राप्त करने की हमारी क्षमता हमारी सभ्यता की सुंदरता और परीक्षा होगी।

.....महात्मा गांधी

सम्पादकीय

जिम्मेदार तन्त्र की जवाबदेही तय होनी चाहिये

इस बार हिमाचल में बरसात ने जिस तरह का कर बरपाया है और उससे जो बुनियादी सवाल खड़े हुये हैं उन पर समय रहते गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां को घटते समय नहीं लगेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि यदि समय रहते सही कदम नहीं उठाये गये तो प्रदेश देश के मानचित्र से गायब हो जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय की इस चिन्ता के बाद एन.जी.टी. ने भी एक समाचार का संज्ञान लेते हुये टी.सी.पी., शहरी विकास, पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी और क्लाइमेट चेंज, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा देहरादून स्थित पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी करके अनियन्त्रित निर्माणों पर उनके जवाब तलब किये हैं। यह चिन्ता और संज्ञान अपने में बहुत गंभीर है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद यह लगा था कि विधानसभा सत्र में समूचा सदन इस भविष्य के सवाल पर गंभीरता से चिन्तन करेगा। परन्तु ऐसा हो नहीं सका है। हमारे माननीय केवल केन्द्र से प्रदेश को आपदा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के प्रस्ताव तक ही सीमित रहे हैं। एन.जी.टी. ने जिस तरह से सारे संबद्ध विभागों से जवाब तलब किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सारे विभाग कहीं न कहीं अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं। यह विभाग अपनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभा पायें हैं? राजनीतिक दबाव कितना हावी रहा है यह स्थितियां अब स्पष्ट होने का वक्त आ गया है।

स्मरणीय है कि 1971 में किन्नौर में आये भूकंप का असर शिमला के लक्कड़ बाजार और रिज तक पड़ा था। लक्कड़ बाजार कितना धंस गया था यह आज भी देखा जा सकता है। रिज को संभालने का काम तब से आज तक चल रहा है और आज रिवाली मार्केट को खतरा पैदा हो गया है क्योंकि जिस तरह का निर्माण उस क्षेत्र में चल रहा है यह उसका प्रभाव है। शिमला में अवैध निर्माणों को बहाल करने के लिये नौ बार रिटेंशन पॉलिसीयां लायी गयी। एन.जी.टी. में मामला गया था और एन.जी.टी. ने स्पष्ट निर्देश दिये थे की अढ़ाई मंजिल से ज्यादा का निर्माण नहीं किया जायेगा? यदि आज एन.जी.टी. के फैसले के बाद हुये निर्माणों की ही सही जानकारी ली जाये तो पता चल जायेगा कि इस फैसले का कितना पालन हुआ है। चंबा में रवि अपने मूल बहाव से 65 किलोमीटर गायब हो गयी है यह रिपोर्ट प्रदेश के तत्कालिक वरिष्ठ नौकरशाह अभय शुक्ला की है। प्रदेश उच्च न्यायालय को भी यह रिपोर्ट सौंपी गयी थी। लेकिन इस रिपोर्ट पर कितना अमल हुआ है? शायद कोई अमल नहीं हुआ है और आज चंबा में रवि के कारण हुआ नुकसान सबके सामने है।

इस बार जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दशकों तक नहीं हो पायेगी। सरकार पहले ही कर्ज के आसरे चल रही हैं। बादल फटने की जितनी घटनाएं इस बार हुई है इतनी पहले कभी नहीं हुई हैं। यह घटनाएं उन क्षेत्रों में ज्यादा हुई हैं जो जल विद्युत परियोजनाओं के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। बहुत सारी परियोजनाएं स्वयं खतरे की जद़ में आ गयी हैं। इसलिये यह चिन्तन का विषय हो जाता है की क्या इस तरह की बड़ी परियोजनाएं प्रदेश हित में हैं। जल विद्युत परियोजनाएं, फोरलेन सड़कों का निर्माण और धार्मिक पर्यटन की अवधारणा क्या इस प्रदेश के लिये आवश्यक है? क्या यह प्रदेश बड़े उद्योगों के लिए सही है। जितना जान माल का नुकसान इस बार हुआ है उससे यह चर्चा उठ गयी है कि इस देवभूमि से देवता अब रूष्ट हो गई हैं। इस चर्चा को नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। क्योंकि देव स्थलों को पर्यटन स्थल नहीं बनाया जा सकता।

एन.जी.टी. ने जितने विभागों से रिपोर्ट तलब की है उन सारे विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से यह शपत पत्र लिये जाने चाहिये कि उन्होंने स्वयं निर्माण मानकों की अवहेलना तो नहीं की है। इसी के साथ शीर्ष प्रशासन और राजनेताओं से भी यह शपथ पत्र लिये जाने चाहिये कि उन्होंने मानकों की कितनी अवहेलना की है। क्योंकि जब तक जिम्मेदार लोगों को जवाब देह नहीं बनाया जायेगा तब तक यह विनाश नहीं रुकेगा।

भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति

अश्विनी वैष्णव
रेल, सूचना एवं प्रसारण,
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

शुरुआती दिनों में कंप्यूटर भारी-भरकम मशीनें हुआ करती थीं, जो लगभग एक कमरे के आकार जितनी होती थीं। उनमें हजारों वैक्यूम टयूब लगती थीं, जो उस समय 'ऑन-ऑफ' स्विच की तरह काम करती थीं। वे आज के आधुनिक और आकर्षक उपकरणों की बजाये पुराने टेलीफोन एक्सचेंज जैसे दिखते थे।

आज समय बदल चुका है। अब अरबों ट्रांजिस्टर वाले, एक नाखून से भी छोटे चिप में कहीं अधिक शक्ति समाई हुई है। ये चिप्स आपके मोबाइल फोन, कार, ट्रेन, फ्रिज, टीवी, स्कूटी, फैक्ट्री मशीनों, हवाई जहाजों को चलाते हैं और अंतरिक्ष में उपग्रहों को भी दिशा दिखाते हैं।

ये इतने छोटे हो गए हैं कि अब आपकी उंगली में पहनी जाने वाली स्मार्ट रिंग में भी फिट होकर आपके दिल की सेहत तक नापते हैं। यही तो सेमीकंडक्टर का जादू है।

विकास का इंजन

किसी भी राष्ट्र की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वह अपने विकास के प्रमुख क्षेत्रों में महारत हासिल करे। इन प्रमुख क्षेत्रों में स्टील, बिजली, दूरसंचार, रसायन, और परिवहन शामिल हैं। सेमीकंडक्टर भी एक ऐसा ही अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

यह लगभग हर चीज़ के अंदर छुपा है, जिनका हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो स्मार्टफोन, कार, ट्रेन, मेडिकल डिवाइस हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर रक्षा प्रणाली, पावर ग्रिड, सैटेलाइट।

जिस तरह से स्टील के बिना कारखाने, पुल और रेल मार्ग नहीं बन सकते, उसी तरह से सेमीकंडक्टर के बिना डिजिटल अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। इनके बिना आधुनिक संचार, डेटा प्रोसेसिंग, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा या सुरक्षित रक्षा प्रणाली की कल्पना नहीं की जा सकती।

जो देश सेमीकंडक्टर का डिजाइन और उत्पादन नहीं कर सकता, वह स्वास्थ्य से लेकर सुरक्षा तक अपनी आवश्यक सेवाओं के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। इसलिए, सेमीकंडक्टर में मज़बूती पाना सिर्फ़ उद्योग की बात नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को आकार देने का सवाल है।

रणनीतिक और वैश्विक राजनीतिक जरूरत

कोविड-19 महामारी ने हमें सेमीडंक्टर की अहमियत बताई। उस समय जब चिप की ग्लोबल सप्लाई चेन डगमगाई तो तमाम उद्योगों का उत्पादन प्रभावित होने से अरबों का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा असर ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग डिवाइस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर पड़ा।

आज सेमीकंडक्टर वैश्विक राजनीति के केंद्र में हैं। चिप बनाने का काम अभी सिर्फ़ कुछ गिने-चुने देशों में ही होता है। इसलिए ज़रा-सी रुकावट पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। कहीं बिजली गुल हो जाए या किसी फैक्ट्री में हादसा हो जाए, तो सप्लाई ठप पड़ सकती है और उद्योग, अर्थव्यवस्था व सुरक्षा सब प्रभावित हो जाते हैं।

हाल में रेयर अर्थ मैग्नेट पर बढ़ता ध्यान हमें याद दिलाता है कि किस तरह महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण वैश्विक शक्ति का स्वरूप तय करता है। उसी तरह, सेमीकंडक्टर भी आज के डिजिटल युग का सबसे अहम संसाधन बन चुके हैं।

बढ़ती मांग:

आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की मांग और तेज़ी से बढ़ेगी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की खपत और उत्पादन तेज़ी से बढ़ रहा है। आज हमारे पास 65 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूज़र्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सालाना 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

साथ ही, हम एआई आधारित सिस्टम, डाटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन भी विकसित कर रहे हैं, जिनमें चिप्स की ज़रूरत होती है। सेमीकंडक्टर की मांग और नवाचार-दोनों में तेज़ बढ़ोतरी से यह ज़रूरी हो जाता है कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में अपनी मज़बूत जगह बनाए।

मौका गंवाने से भविष्य संवारने तक

दशकों तक यह कहा जाता रहा कि सेमीकंडक्टर की दौड़ में भारत पीछे छूट गया है। अब यह बात सच नहीं रही।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 10 चिप प्रोजेक्ट को मंज़ूरी दी गई है और निर्माण तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है।

आज हम आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि इस साल पहला 'मेड इन इंडिया' चिप बाज़ार में आ जाएगा।

गुजरात के साणंद में एक यूनिट में पायलट प्रोडक्शन लाइन शुरू हो चुकी है और अगले एक साल में चार और यूनिट्स के उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है।

एप्लाइड मटेरियल्स, लैम रिसर्च, मर्क और लिंडे जैसी ग्लोब कंपनियां भी भारत में फैक्ट्रियों और सप्लाई चेन को मज़बूत बनाने में निवेश कर रही हैं। यह इकोसिस्टम अप्रोच प्रधानमंत्री की उस सोच को दर्शाता है, जिसके अंतर्गत भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग मज़बूती से और लंबे समय तक आगे बढ़ सके।

इतने कम समय में मिली इस बड़ी सफलता के पीछे कई कारण हैं -प्रधानमंत्री की स्पष्ट दृष्टि, क्रियान्वयन पर खास ध्यान, पेशेवरों के हाथों में फैसले देना, वैश्विक सहयोग और राज्य सरकारों का मज़बूत समर्थन। विकास की इस दौड़ में भारत मज़बूत क़दमों से आगे बढ़ रहा है और भविष्य का नेतृत्व करने को तैयार है। इस बदलाव में हमारी डिज़ाइन क्षमता और प्रतिभा अहम भूमिका निभा रही हैं।

डिज़ाइन और प्रतिभा: भारत की ताकत

भारत की असली ताकत उसके लोग हैं। इस ताकत का सही उपयोग करने के लिए नीतियां और निवेश बेहद ज़रूरी हैं। भारत के पास आज वैश्विक सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कार्यबल का 20% से अधिक हिस्सा है।अनुमान है कि अगले दशक की शुरुआत तक दुनिया को 10 लाख से ज़्यादा सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल्स की कमी होगी। भारत इस कमी को पूरा करने की तैयारी कर रहा है।

सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए विश्वस्तरीय इलेक्ट्रानिक डिजाइन ऑटोमेशन(ईडीए) टूल्स का उपयोग 350 संस्थाओं और स्टार्टअप्स के 60,000 से अधिक लोग कर रहे हैं। 2025 में ही इनका इस्तेमाल 1.2 करोड़ घंटे से अधिक हो चुका है।

सरकार के सपोर्ट से स्टार्टअप्स भारत के चिप डिज़ाइन इकोसिस्टम को नई ऊर्जा दे रहे हैं। माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज़ ऐसी आईओटी (IoT) चिप्स बना रही है, जो आईआईटी मद्रास में विकसित किए गए स्वदेशी 'शक्ति प्रोसेसर' पर आधारित हैं। नेत्रसेमी नामक स्टार्टअप ने हाल ही में 107 करोड़ रु की रिकॉर्ड फंडिंग हासिल की है, जो अब तक भारत के डिज़ाइन स्पेस में सबसे बड़ा निवेश है। कई ऐसे स्टार्टअप सरकार की डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के तहत विकसित हो रहे हैं।

क्लासरूम से क्लीनरूम तक

मोहाली की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी (एससीएल) में 17 कॉलेजों के छात्रों ने अब तक 20 चिप्स बना लिए हैं। आने वाले महीनों में और भी चिप्स तैयार किए जाएंगे। इस तरह की प्रतिभा का विकास भारत को सेमीकंडक्टर सेक्टर में मज़बूत स्थान दिलाएगा।

एससीएल को भी आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि यंग इनोवेटर्स के सपने पूरे हो सकें और भारत की प्रतिभा क्लासरूम से निकलकर क्लीनरूम तक पहुंच सके।

ग्लोबल कंपनियां भी भारतीय प्रतिभा में निवेश कर रही हैं। लैम रिसर्च भारत में 60,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षित करेगी। एप्लाइड मटेरियल्स, एएमडी और माइक्रोचिप रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) में 1.1 बिलियन डॉलर निवेश कर रहे हैं। आईआईएससी, आईआईटी और अन्य संस्थानों के साथ साझेदारी से एक मज़बूत 'लैब से फैक्ट्री तक' कार्यबल तैयार हो रहा है।

भारत अमेरिका, जापान, यूरोपीय संघ और सिंगापुर जैसे साझेदारों के साथ मिलकर भविष्य के लिए तैयार कौशल भी विकसित कर रहा है। इस तरह स्थानीय प्रतिभा और वैश्विक सहयोग का मेल भारत को केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए निर्माण करने में सक्षम बना रहा है।

डिजिटल इंडिया से सेमिकॉन इंडिया तक

भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े विज़न का हिस्सा है। यह डिजिटल इंडिया से शुरू हुई, जिसने डिजिटल ढांचा बनाया और नागरिकों को सशक्त किया। इंडिया स्टैक, यूपीआई, आधार और टेलीकॉम नेटवर्क ने हर भारतीय को तकनीक उपलब्ध कराई। साथ ही, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन इकोसिस्टम को भी मज़बूत किया। अब हम सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और उपकरणों के निर्माण का इकोसिस्टम बना रहे हैं। आज से शुरू हो रहा सेमिकॉन इंडिया समिट 2025 इस यात्रा का ही अगला पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे ।

इस साल 48 देशों से 500 से ज़्यादा ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर इसमें भाग ले रहे हैं, जबकि पिछले साल केवल लगभग 100 नेता शामिल हुए थे। पूरी दुनिया हमारे दरवाज़े पर इसलिए आ रही है क्योंकि अनिश्चितताओं से जूझ रही दुनिया के लिए स्थिर भारत ही आशा की किरण है।

जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और मलेशिया के विशेष पवेलियन सहयोग को और गहरा बनाएंगे। इसके अलावा, इसमें उद्योग जगत और दुनिया भर की युवा प्रतिभाओं के बीच बिजनेस टू बिजनेस (B2B) चर्चा, समझौता ज्ञापन और साझेदारियां भी होंगी।

प्रोडक्ट नेशन

हमारा लक्ष्य भारत को 'प्रोडक्ट नेशन' बनाना है। हमारी सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियों से निकलने वाले चिप न केवल भारत बल्कि दुनिया के टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, डाटा सेंटर, कंज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम क्षेत्रों की ज़रूरत पूरी करेंगे।

आने वाले दशक में, जैसे-जैसे हमारी सेमीकंडक्टर इकाइयां विकसित होकर बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लगेंगी, भारत पूरे सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी केंद्र बनकर उभरेगा।

मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं मां त्रोकड़ावाली, पत्थर फाड़कर प्रकट हुई थी मां की दिव्य मूर्ति

शिमला। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहां हर पर्वत, हर घाटी और हर क्षेत्र में कोई न कोई देवता या देवी विराजमान हैं। मंडी जिले की मंडी-कोटली मार्ग पर स्थित श्री त्रोकड़ाधाम भी ऐसा ही एक पावन स्थान है, जहां मां त्रोकड़ावाली की अनूठी महिमा, भक्तों की अटूट श्रद्धा और अद्भुत चमत्कारों की कहानियां प्रचलित हैं। यह धाम केवल पूजा-अर्चना स्थल नहीं, बल्कि भक्ति, साहस और तपस्या की अमर पाठशाला है। यहां आने वाला हर भक्त मां की दिव्य छत्रछाया को अनुभव करता है। यही कारण है कि यह धाम आज श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है।

तुंगल घाटी की सुरम्य वादियों में बसा त्रोकड़ा धाम

आस्था और श्रद्धा का जीवंत प्रतीक है। मान्यता है कि मां अंबिका माता नाउ-पनाऊ की कृपा से दुर्गा रूप में एक पत्थर से प्रकट हुई और उनके एक अनोखे भक्त और देवी मां के अद्भुत आशीर्वाद से इस धाम की स्थापना हुई।

उत्पत्ति की कथा

मां त्रोकड़ा वाली का प्राकटय कब और कैसे हुआ, इस बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। ग्रामीण मान्यताओं के अनुसार, सैकड़ों वर्ष पहले एक साधक ने इस स्थान पर गहन तपस्या की थी। मां ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि यह भूमि भविष्य में श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनेगी। समय के साथ यहां मां की महिमा का प्रसार हुआ और धीरे-धीरे यह स्थल एक सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया।

भक्तों का मानना है कि यहां मां की पूजा-अर्चना करने से संकट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

त्रोकड़ा धाम के इतिहास का ताना-बाना मां दुर्गे और उनके सच्चे सेवक श्री लाभ सिंह धरवाल से भी जुड़ा

है। गांव साई, तहसील कोटली, जिला मंडी निवासी लाभ सिंह जी का जीवन कठिन परिश्रम, तपस्या और मां के प्रति अटूट आस्था का उदाहरण है। बकौल लाभ सिंह त्रोकड़नाला में डंगे के निर्माण कार्य के दौरान एक भारी पत्थर किसी से हिलाया नहीं जा रहा था। जब ठेकेदार ने उसे तोड़ने के निर्देश दिए तो यह दो भागों में टूटा और बीच से माता की भव्य मूर्ति निकली। यह मूर्ति आज भी मंदिर में स्थापित है।

जब भक्त ने ली मां की परीक्षा

माता जब त्रोकड़ नाला में प्रकट हुई तो लोगों को विश्वास दिलाने के लिए भक्त लाभ सिंह ने मां से अरदास की कि माता अगर आप सचमुच में यहां स्थाई रूप से प्रकट हो गई हैं तो मैं तभी मानूंगा अगर आप आधे घंटे में बारिश करोगी। आसमान साफ था, 40-50 लोगों के सामने मैंने बारिश के लिए अरदास तो लगा दी लेकिन, मन थोड़ा आशंकित था। पूजा आरती करके सभी अपने घरों को निकल गए। जैसे ही में घर पहुंचा साफ आसमान में बादल छाये, अचानक बिजली चमकी और बरसात शुरू हो गई।

त्रोकड़ा नाला से त्रोकड़ा धाम का नाम कैसे पड़ा

त्रोकड़ा नाला से त्रोकड़ा धाम नाम इसलिए पड़ा, क्योंकि धामों से चीरकाल से ही मनुष्य को, अपनी इच्छाओं की पूर्ति से लेकर, गति व मोक्ष तक प्राप्त होता है। इसलिए महामायी त्रोकड़ा की कृपा से अब वहीं पर ही पितरों का उद्धार, संतान प्राप्ति, भूत-प्रेत साया को दूर करना, नवग्रहों की शान्ति संबंधी अनुष्ठान किए जाते हैं। यहां नशीले पदार्थ पूरी तरह से त्याज्य हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के पूछ-प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। विशेष बात यह कि उनका विवरण लिखित रूप में रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। यहां आज प्राणी, पशु, पक्षी की बलि प्रथा से हटकर केवल एक ही नारियल से सभी कार्यो को सफल किया जाता है। इसके बहुत से प्रमाण जो मन्दिर में हस्त लिखित रजिस्टर में दिनांक सहित दर्ज किये जाते हैं।

पुजारी लाभ सिंह की भक्ति

लाभ सिंह जी ने 1960 के दशक से मां की भक्ति आरंभ की। अंबिका माता नाउ-पनाऊ के अनन्य भक्त कई वर्षों तक कठिन परीक्षाओं से गुजरे, कभी बीमारी, कभी आर्थिक तंगी, तो कभी पारिवारिक संकट। फिर भी वे मां के दरबार तक पहुंचने के लिए लहूलुहान पैरों से भी पैदल यात्रा करते।

मां ने उन्हें स्वप्नों और दृष्टांतों में दर्शन दिए। एक बार सपने में उन्होंने देखा कि भव्य मंदिर में मां दुर्गा सिंह (शेर) पर विराजमान हैं। मां ने संकेत दिया कि यही उनका धाम होगा।

मंदिर निर्माण की चुनौतियां

धाम की स्थापना आसान नहीं थी। पैसों की कमी, आलोचनाएं और प्रशासनिक दिक्कतों ने मार्ग रोका। फिर भी पुजारी जी ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे-धीरे भक्तों का सहयोग मिला और मंदिर निर्माण संभव हुआ। मंदिर में हर वर्ष भाद्रपद कृष्णपक्ष की चतुर्दशी को जाग होती है जिसमें माता के गूर देववाणी करते हैं। श्रद्धालुओं की ओर से भजन-कीर्तन व भंडारे का आयोजन भी किया जाता है।

आज का त्रोकड़ा धाम

आज त्रोकड़ा धाम हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहां नियमित रूप से भजन-कीर्तन, भंडारे और धार्मिक आयोजन होते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। धाम के प्रांगण में प्रवेश करते ही एक अलौकिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। श्री त्रोकड़ाधाम केवल एक मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह भक्ति, त्याग और दिव्यता का जीवंत प्रतीक है। यहां की हर ईंट और हर पत्थर मां की महिमा के साक्षी हैं। यह धाम हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास में निहित है।

भक्त व भगवान के सच्चे रिश्ते का सजीव उदाहरण

त्रोकड़ा धाम आज न केवल श्रद्धा का प्रतीक बना है, बल्कि भक्त और भगवान के रिश्ते का सजीव उदाहरण भी है। यहां आकर हर भक्त को मां के अलौकिक दर्शनों के साथ ही उनका आशीष प्राप्त होता है।

कार-बिन बना एचआईवी, नशामुक्ति और स्वच्छता के संदेश का सारथी

शिमला। समाज में एचआईवी नियंत्रण, नशामुक्ति और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी ने एक अभिनव पहल की है। इसके तहत टैक्सी चालकों को कार-बिन (कार में रखने योग्य छोटे डस्टबिन) वितरित किए जा रहे हैं। कार-बिन जहां एक ओर गाड़ियों में सफर के दौरान कचरे के निपटान का काम करेंगे, वहीं एचआईवी, नशामुक्ति और स्वच्छता के संदेश के सारथी भी बनेंगे।

इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा गत 12 अगस्त को किया गया था। अभियान के पहले चरण में लगभग 4 लगभग लगभग 40 टैक्सी चालकों को कार-बिन वितरित किए गए। इस कार्य में करसोग अस्पताल में तैनात आईसीटीसी काउंसलर नंदा शर्मा ने विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि एड्स कंट्रोल सोसायटी के निदेशक राजीव कुमार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में एचआईवी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। साथ ही लोगों को नशामुक्त और स्वच्छ जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है।

एचआईवी के प्रसार को रोकने और लोगों में जागरूकता लाने के लिए

हजार कार-बिन वितरित किए गए, जबकि दूसरे चरण में लगभग 6 हजार कार-बिन बांटने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पहल से जुड़कर स्वस्थ और जागरूक समाज निर्माण में योगदान दे सकें।

प्रदेश सरकार के निर्देशों पर एड्स कंट्रोल सोसायटी के निदेशक राजीव कुमार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान की अवधि एक माह निर्धारित की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 6 हजार गांवों में टैक्सी चालकों को कार-बिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। विचार यह है कि टैक्सी चालक रोजाना बड़ी संख्या में लोगों से मिलते हैं और सफर के दौरान यात्रियों से निरंतर संपर्क में रहते हैं। ऐसे में उनके वाहनों में लगे कार-बिन सवारियों का ध्यान न केवल स्वच्छता की ओर आकर्षित करेंगे बल्कि, एचआईवी और नशे के खिलाफ भी सकारात्मक संदेश देंगे।

इस पहल के अंतर्गत करसोग क्षेत्र में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिस नई रणनीति से प्रदेश काम कर रहा है, उसकी सराहना अब अन्य राज्यों में भी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी की रणनीति अब देशभर में मॉडल बनकर उभरी है। यही कारण है कि अनेक राज्य हिमाचल की रणनीतिक पहल का अनुसरण करने लगे हैं। यह उपलब्धि न केवल प्रदेश के लिए गौरव की बात है बल्कि यह दर्शाती है कि छोटे-छोटे प्रयास भी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा असर डाल सकते हैं।

अभियान की मुख्य विशेषता यह है कि यह केवल सरकारी पहल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जन भागीदारी को केंद्र में रखा गया है। टैक्सी चालक, जो आमतौर पर स्वास्थ्य अभियानों का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं बनते, अब इस प्रयास में सक्रिय सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। उनका हर सफर केवल यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने का साधन नहीं रहेगा, बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और नशा मुक्ति का संदेश लेकर चलेगा।

हिमालय क्षेत्र में बढ़ती आपदाओं की तीव्रता

राजन कुमार शर्मा

हिमालय विश्व की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, जो लगातार भू-वैज्ञानिक रूप से सक्रिय है। यही कारण है कि यह क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। हाल के दशकों में यहांआपदाओं की संख्या और तीव्रता दोनों बढ़ी हैं।

आपदाओं की बढ़ती तीव्रता के कारण:

प्राकृतिक कारण: भूवैज्ञानिक सक्रियता : हिमालय ज़ोन-IV और V में आता है, इसलिए बड़े भूकंप की आशंका हमेशा रहती है। **जलवायु परिवर्तन:** औसत तापमान में वृद्धि से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, असमान्य वर्षा पैटर्न, बादल फटना, लंबे समय तक भारी वर्षा, भूस्खलन प्रवण ढलानें: ढलानों की प्राकृतिक अस्थिरता।

मानवजनित कारण: अनियंत्रित सड़क व सुरंग निर्माण : बिना भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स: नदी तट और ढलानों की अस्थिरता बढ़ाते हैं, वनों की कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन: प्राकृतिक अवरोध खत्म होने से भूस्खलन व बाढ़ का खतरा बढ़ा, पर्यटन व शहरीकरण का दबाव: अतिक्रमण और अव्यवस्थित बस्तिया। आपदाओं के प्रमुख रूप: भूस्खलन : हर साल मानसून में सैकड़ों स्थान प्रभावित, सड़कें व गांव कट जाते हैं, अचानक बाढ़: बादल फटने से कुछ ही घंटों में भारी विनाश उदाहरण 2010 लद्दाख, 2021 उत्तराखंड, भूकंप : ऐतिहासिक रूप से बड़े भूकंप (1905 कांगड़ा, 2015 नेपाल ने) व्यापक तबाही मचाई, हिमस्खलन : सैनिक व स्थानीय लोग लगातार प्रभावित होते हैं, ग्लेशियर झील फटना (GLOFs : 2013 केदारनाथ और 2021 ऋषि गंगा जैसी घटनाएं। बढ़ती तीव्रता के प्रभाव: मानव जीवन : हर साल हजारों जानें जाती हैं, आर्थिक हानि : सड़कें, पुल, बिजली परियोजनाएं व कृषि प्रभावित, पर्यटन पर असर : चारधाम यात्रा, हिमाचल व कश्मीर पर्यटन प्रभावित, सामाजिक विस्थापन : गांव उजड़ते हैं, लोगों को पुनर्वासित करना पड़ता है, पर्यावरणीय क्षति : नदियों का मार्ग बदलना, भूमि क्षरण, जैव विविधता प्रभावित। निवारण एवं प्रबंधन: सतत विकास की योजना: भू-वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अध्ययन के आधार पर निर्माण कार्य, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना, स्थानीय समुदाय की भागीदारी: ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, वनों व पारिस्थितिकी का संरक्षण, भूमि उपयोग पर कड़ा नियमन: संवेदनशील क्षेत्रों में अवैज्ञानिक निर्माण पर रोक। जलवायु अनुकूलन नीतियां: वर्षा जल प्रबंधन, ग्लेशियर मॉनिटरिंग।

हिमालय क्षेत्र में आपदाओं के समाधान, नीति और योजना स्तर, सतत विकास सड़क, सुरंग, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट आदि का निर्माण भू-वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यावरणीय मंज़ूरी के बाद ही हो, भूमि उपयोग नियंत्रण संवेदनशील ढलानों और नदी किनारों पर अनियंत्रित निर्माण पर रोक, कानूनी ढांचा सख्त करना आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भवन निर्माण संहिता का अनिवार्य पालन, हरित नीति पुनर्वनीकरण, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट और नदी तट प्रबंधन, तकनीकी और वैज्ञानिक उपाय, अर्ली वार्निंग सिस्टम, मौसम पूर्वानुमान, क्लाउडबर्स्ट और ग्लेशियर मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट और रडार तकनीक, भूस्खलन प्रवण क्षेत्रें में सेंसर आधारित अलार्म सिस्टम, ग्लेशियर व झील मॉनिटरिंग रोकने हेतु झीलों का नियमित निरीक्षण, सुदृढ़ निर्माण तकनीक ढलानों पर रिटेनिंग वॉल, बायो-इंजीनियरिंग और सुरक्षित भवन डिज़ाइन, डेटा बेस और मैपिंग उच्च जोखिम क्षेत्रों की भू-वैज्ञानिक एवं आपदा संवेदनशीलता मैपिंग।

समुदाय और स्थानीय स्तर आपदा शिक्षा व जागरूकता ग्राम स्तर पर मॉक ड्रिल, प्राथमिक चिकित्सा और आपदा प्रतिक्रिया प्रशिक्षण, स्थानीय भागीदारी गाँवों में स्वयंसेवी समूह बनाना, पारंपरिक ज्ञान का उपयोग पहाड़ी घरों की पारंपरिक वास्तुकला व जल प्रबंधन तकनीक का संरक्षण, सुरक्षित आजीविका स्थानीय लोगों को ऐसी जीविका विकल्प जैसे ईको-टूरिज्म, जैविक खेतीऋदेना जो पर्यावरण पर कम दबाव डालें।

जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ वर्षा जल संचयन और लघु सिंचाई प्रणालियाँ, पर्वतीय नदियों का प्राकृतिक बहाव बनाए रखना, ग्लेशियर और वनों के संरक्षण को विकास योजनाओं से जोड़ना, नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक निवेश ताकि जलविद्युत परियोजनाओं का दबाव घटे।

प्रशासनिक व आपदा प्रबंधन उपाय: जिला व राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाएँ समय-समय पर अपडेट हों, रेस्क्यू, राहत और पुनर्वास के लिए त्वरित बल की तैनाती, मोबाइल ऐप और डै आधारित चेतावनी प्रणाली, प्रभावित परिवारों के लिए बीमा व राहत पैकेज।

निष्कर्ष: हिमालय क्षेत्र में आपदाओं की तीव्रता बढ़ना केवल प्राकृतिक कमजोरी का परिणाम नहीं है, बल्कि मानवजनित दबाव और जलवायु परिवर्तन भी इसके बड़े कारण हैं। यदि विकास को पारिस्थितिक संतुलन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न जोड़ा गया तो भविष्य में आपदाएँ और भी घातक रूप ले सकती हैं।हिमालय क्षेत्र में आपदाओं का पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। क्योंकि यह भौगोलिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है। लेकिन वैज्ञानिक योजना, पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी से इनकी तीव्रता और नुकसान दोनों को कम किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने दिये राहत – बचाव कार्य तेज करने के निर्देश

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला पहुंचते ही प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और उससे हुए नुकसान की स्थिति की समीक्षा की। सरकारी आवास ओक ओवर पहुंचने के बाद उन्होंने मुख्य सचिव से विस्तृत जानकारी ली। मुख्य सचिव ने उन्हें प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और वहां उठाये जा रहे कदमों से अवगत करवाया।

मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि लोगों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें, सतर्क रहें और नदी – नालों के किनारे जाने से बचें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में फिलहाल मूसलाधार बारिश जारी है। ऐसे में सभी लोग सावधानी बरतें और मुश्किल में फंसे लोगों की मदद करने में सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने शनिवार को आपदा प्रभावित चंबा और कांगड़ा जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया था। आज उनका कुल्लू जिला जाने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम इसमें बाधा बना। ऐसे में उन्हें चंडीगढ़ से सड़क मार्ग से शिमला लौटना पड़ा।

डॉ.वाई.एस.परमार को भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव विधानसभा के मानसून सत्र में सर्वसम्मति से पारित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल निर्माता स्व. डॉ.यशवंत सिंह परमार को भारत रत्न सम्मान दिये जाने की मांग को लेकर एक ऐतिहासिक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। नाहन के विधायक अजय सोलंकी ने नियम 101 के तहत गैर – सरकारी कार्य संकल्प सदन में पेश किया, जिसे पक्ष और विपक्ष दोनों दलों ने एकजुट होकर समर्थन दिया। इस दौरान सभी विधायकों ने राजनीति से ऊपर उठकर डॉ. परमार के योगदान को याद किया और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की सिफारिश केंद्र सरकार से करने का आहवान किया।

डॉ. यशवंत सिंह परमार का जन्म 4 अगस्त 1906 को हुआ था जबकि 2 मई 1981 को उनका देहांत हो गया। हिमाचल प्रदेश के गठन और विकास में उनके असाधारण योगदान को देखते हुए उन्हें 'हिमाचल निर्माता', 'संस्थापक' या 'निर्माता' कहा जाता है। डॉ. परमार ने ही छोटी – छोटी पहाड़ी रियासतों को एकजुट कर हिमाचल प्रदेश की नींव रखी और प्रदेश की संस्कृति, अस्मिता और पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। वे न केवल हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री बने बल्कि अपने सादगीपूर्ण जीवन, दूरदर्शिता और जनता के प्रति समर्पण के लिए हमेशा याद किए जाते हैं।

संकल्प प्रस्तुत करते हुए विधायक अजय सोलंकी ने कहा कि डॉ. परमार ने प्रदेश को अस्तित्व दिलाने के साथ ही विकास की मजबूत नींव रखी। उनकी दूरदृष्टि से ही आज हिमाचल एक अलग पहचान रखता है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और डॉ.परमार इसके पूर्ण रूप से पात्र हैं।

सदन में संकल्प पर चर्चा के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि डॉ. परमार बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, मुख्यमंत्री होते हुए भी एचआरटीसी की बसों में सफर करते और रेस्ट हाउसों में रुकते थे। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने उन्हें जनजातीय लोगों का मसीहा बताया और कहा कि उन्होंने पैदल यात्राएं कर गांव – गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनीं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि अगर हिमाचल को किसी अन्य राज्य में मिला दिया जाता तो प्रदेश की संस्कृति खत्म हो जाती लेकिन डॉ. परमार की दूरदृष्टि ने हिमाचल की अलग पहचान कायम रखी।

भाजपा विधायक सुखराम चौधरी ने कहा कि इतिहास केवल घटनाओं से नहीं बल्कि महापुरुषों से बनता है और डॉ. परमार ऐसे ही महापुरुष थे। विधायक हंसराज ने कहा कि डॉ. परमार की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जानी चाहिए ताकि नई पीढ़ी उनके बारे में जान सके। कांग्रेस विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि राजनीति को उन्होंने कभी सत्ता का साधन नहीं बनाया बल्कि जनता की सेवा को प्राथमिकता दी। भाजपा विधायक रीना कश्यप ने कहा कि जिस पंचायत से उनका ताल्लुक था वहां विकास के विशेष कार्य होने चाहिए और उनके पैत्रिक गांव को आदर्श पंचायत घोषित किया जाना चाहिए।

कांग्रेस विधायक नीरज नैय्यर ने कहा कि डॉ. परमार ने आजादी से पहले ही लाहौर में पहाड़ी राज्य की परिकल्पना की थी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि भारत रत्न का सम्मान डॉ. परमार को मिलना चाहिए और उनकी जयंती को भव्य तरीके से मनाया जाना चाहिए। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि डॉ. परमार का जीवन सादगी से भरा था और वे चूल्हे के पास बैठकर खाना खाते थे।

संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में उप मुख्यमंत्रे मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि डॉ. परमार को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, उनका इतिहास अपने आप गवाही देता है। उन्होंने कहा कि भू सुधार कानून और धारा 118 उनकी ही देन है, जिनकी वजह से हिमाचल की जमीन आज सुरक्षित है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रस्ताव पारित होने पर सभी विधायकों का धन्यवाद किया और कहा कि देर भले हुई है लेकिन अब यह मांग केंद्र सरकार तक जाएगी और पूरी उम्मीद है कि डॉ. परमार को भारत रत्न प्रदान किया जाएगा।

प्राकृतिक खेती के अग्रदूत और प्रचारक बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

शिमला/शैल। प्राकृतिक कृषि पर आधारित एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र, रिकांग पिओ, किन्नौर द्वारा किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण डॉ. यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी

विश्वविद्यालय, नौणी और आत्मा कार्यक्रम के सहयोग से राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में किन्नौर जिले के 30 सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य इन प्रतिभागियों को सतत और पर्यावरण अनुकूल कृषि तकनीकों की जानकारी और व्यावहारिक कौशल से सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने – अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक कृषि के अग्रदूत और प्रचारक बन सकें।

प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किन्नौर के उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने की। अपने संबोधन में उन्होंने प्राकृतिक कृषि की बढ़ती प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला और व्यापक जागरूकता, वैज्ञानिक प्रमाणिकता और अनुसंधान की आवश्यकता को रेखांकित किया।

केवीके के प्रमुख एवं शारबो केंद्र के सहनिदेशक, डॉ प्रमोद शर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ कृषि पद्धतियों की ओर स्थानांतरण आवश्यक है, जिससे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा हो सके और किसानों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। आत्मा के परियोजना निदेशक डॉ. रमेश लाल ने एनएमएनएफ (NMNF) के तहत चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों को इन योजनाओं तक प्रभावी रूप से पहुँचने और क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया।

बागवानी विभाग, किन्नौर के उपनिदेशक डॉ. बी.एस. नेगी ने भी प्राकृतिक कृषि को सशक्त करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की भूमिका पर बल दिया। प्रशिक्षण समन्वयक डॉ . बुधी राम, केवीके के वैज्ञानिक, आत्मा तथा बागवानी विभाग किन्नौर के अधिकारीगण भी इस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहे। शिक्षण के दौरान, फूड सिस्टम विश्लेषक आशीष गुप्ता ने किसानों को सितारा प्रमाणन के बारे में भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से किसान आसानी से अपना प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक खेती करने वाले प्रगतिशील किसानों ने भी प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव साझा किए

यह प्रशिक्षण पहल प्रतिभागियों को तकनीकी जानकारी और व्यावहारिक दक्षता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे सीआरपी परिवर्तन के उत्प्रेरक बन सकें और हिमाचल प्रदेश में सतत एवं पर्यावरण चेतनशील कृषि प्रणाली के विकास में योगदान दे सकें।

कुल्लू जिला में प्रभावित कुल 506 में से 432 पेयजल योजनाएं बहाल: उप – मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। उप – मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला कुल्लू में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हाल में आई आपदा से कुल्लू जिला बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके चलते जनजीवन अस्त – व्यस्त हो गया है। इस दौरान जल शक्ति विभाग की 708 योजनाओं में से 506 योजनाएं प्रभावित हुई हैं।

उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दिन – रात इन योजनाओं की बहाली कार्यों में लगे हैं, ताकि स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को जल्द से जल्द राहत प्रदान की जा सके। विभाग द्वारा अब तक 432 योजनाएं आंशिक रूप से बहाल की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि शेष योजनाओं की बहाली का कार्य युद्धस्तर पर जारी है और सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र को शीघ्र सामान्य जलापूर्ति की जाए।

उप – मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार जनता के साथ खड़ी है। प्रभावितों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण

शिमला/शैल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत आपदा प्रभावित गाँव रौणी, सुदली, चंबी,

काकडार,भटी का दौरा कर वर्तमान स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया तथा 16 परिवारों को 2 लाख 30 हजार की फौरी राहत प्रदान की।

उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाक़ात कर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने उपमंडलीय प्रशासन को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

तीन दिनों में मणिमहेश यात्रा के लगभग 12 हज़ार से अधिक श्रद्धालु चंबा से रवाना:मुकेश रेपसवाल

शिमला/शैल। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि पिछले तीन

दिनों में श्री मणिमहेश यात्रा के लगभग 12 हज़ार से अधिक श्रद्धालु चंबा से रवाना हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को नूरपुर, पठानकोट तथा भदरवाह तक राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से निशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

उपायुक्त ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से चंबा चौगान में ठहरे जम्मू – कश्मीर से आये सभी श्रद्धालु वापस लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि चौगान में ठहरे रामबन के 11 सदस्यीय एक परिवार को भी एचआरटीसी बस से पठानकोट भेजा गया।

उन्होने बताया कि कुछ श्रद्धालु चंबा में अपने मित्रों व जानकारों के पास मौजूद हो सकते हैं इसके अतिरिक्त जम्मू – कश्मीर से छड़ी यात्रा अथवा लंगर सेवा के साथ आये श्रद्धालुओं के पुलिस ग्राउंड बारगाह में पार्क हुए वाहन अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। मुकेश रेपसवाल ने जानकारी दी कि यात्रा से पैदल बग्गा तक वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा, रहने एवं भोजन के अलावा परिवहन सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि भरमौर – चंबा राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर अलग – अलग स्थानों पर अधिकारियों को तैनात किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा सके।

कुल्लू और लाहौल स्पीति में 7 दिनों के लिए इंट्रा – सर्किल रोमिंग सुविधा सक्रिय

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश लाइसेंस सेवा क्षेत्र (HP LSA) दूरसंचार विभाग के अपर महानिदेशक टेलीकॉम ने सूचित किया है कि जिला चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में इंट्रा – सर्किल रोमिंग (ICR) सुविधा 7 दिनों के लिए, अर्थात 03 सितम्बर 2025 तक के लिए सक्रिय कर दी गई है।

यह पहल प्रभावित क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी को बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। इस क्षेत्र के मोबाइल उपभोक्ता अपने डिवाइस की सेटिंग्स में जाकर किसी भी उपलब्ध मोबाइल नेटवर्क का मैन्युअल रूप से चयन कर सकते हैं, चाहे वह उनके मूल सेवा प्रदाता का नेटवर्क न हो। ICR सुविधा की अवधि के दौरान उपभोक्ता किसी भी ऐसे टेलीकॉम ऑपरेटर के नेटवर्क से जुड़कर सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे जिसकी उस क्षेत्र में कवरेज उपलब्ध है।

इस अस्थायी व्यवस्था का उद्देश्य अत्यधिक बारिश के कारण उत्पन्न व्यवधान के दौरान निर्बाध मोबाइल संचार सुनिश्चित करके सहायता प्रदान करना है।

केन्द्र सरकार द्वारा आपदा प्रभावित राज्यों में हुये नुकसान के आकलन के लिए अंतर – मंत्रालयी केन्द्रीय दलों का गठन

शिमला / शैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रभावित राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के निर्देश पर गृह मंत्रालय (MHA) ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू – कश्मीर में भारी बारिश, बाढ़, अचानक बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर – मंत्रालयी केन्द्रीय दलों (IMCTs) का गठन किया है। ये केन्द्रीय दल मौके पर जाकर स्थिति और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का आकलन करेंगे।

केन्द्रीय दल अगले सप्ताह की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू – कश्मीर के बाढ़ / भूस्खलन प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे, जो मौजूदा मानसून सीजन के दौरान भारी से अत्यधिक भारी बारिश, अचानक बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले ही एक IMCT और एक बहु – क्षेत्रीय दल (Multi-Sectoral Team) दौरा कर चुका है।

इन केन्द्रीय दलों का नेतृत्व गृह मंत्रालय / राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे और इनमें व्यय, कृषि और किसान कल्याण, जल शक्ति, ऊर्जा, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास मंत्रालयों / विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

गृह मंत्रालय इन राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में है और आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें NDRF, सेना और वायु सेना के हेलीकॉप्टरों की तैनाती शामिल है, जो खोज और बचाव कार्यों तथा आवश्यक सेवाओं की बहाली में सहायता कर रहे हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अगस्त 2019 में लिये गये निर्णय के अनुसार, गृह मंत्रालय गंभीर आपदा के तुरंत बाद राज्य सरकारों / केन्द्रशासित प्रदेशों के ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बगैर IMCTs का गठन करता है ताकि मौके पर जाकर नुकसान का आकलन किया जा सके। IMCT द्वारा नुकसान का आकलन करने के बाद, केन्द्र सरकार स्थापित प्रक्रिया के अनुसार NDRF से राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2025 – 26 के दौरान, केन्द्र सरकार ने 24 राज्यों को SDRF में 10,498.80 करोड़ रुपए, 12 राज्यों को NDRF से 1,988.91 करोड़ रुपए, 20 राज्यों को राज्य आपदा शमन निधि (SDMF) से 3,274.90 करोड़ रुपए और 09 राज्यों को राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF) से 372.09 करोड़ रुपए जारी किए हैं, ताकि आपदा प्रभावित राज्य प्रभावित लोगों को तत्काल राहत सहायता प्रदान की जा सके।

मणिमहेश में आपदा से हुये नुकसान पर लोगों के आरोपों का सच बताये सरकार: जयराम ठाकुर

शिमला / शैल। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सोशल मीडिया में प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार मणिमहेश में हुए जान माल के नुकसान का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वह अधिकारिक आंकड़ों से बहुत ज्यादा है। ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें स्वयं को तीर्थ यात्री बताने वाले श्रद्धालुओं द्वारा कहा जा रहा है कि क्लाउडबर्स्ट की वजह से वहां पर जान माल की बहुत क्षति हुई है। ऐसे वीडियो में लोगों द्वारा बहुत लोगों के आपदा की चपेट में आने से मौत होने की बात भी कही जा रही है। सरकार द्वारा इस पर कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया गया है। वहां से जो भी वीडियो आ रहे हैं वह सरकार की नाकामी और कुप्रबंधन से जुड़े हुए ही आ रहे हैं। लोगों को राहत प्रदान करने के हर सरकारी दावे को मौके पर मौजूद श्रद्धालु खारिज कर रहे हैं। लोगों के आरोप और सरकार के दावे के बीच जमीन आसमान का अंतर है। बिजली और संचार सुविधाएं ध्वस्त होने के कारण वहां का सही अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री मणिमहेश यात्रा के श्रद्धालुओं से जुड़े और लोगों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करें।

15000 मणिमहेश तीर्थयात्री भरमौर से घर वापसी के लिए रवाना: डॉ जनक राज

शिमला / शैल। भूस्खलन, बादल फटने और सड़कों के बह जाने से मणिमहेश यात्रा अस्त – व्यस्त हो गई है, ऐसे में भरमौर विधायक डॉ. जनक राज ने फंसे हुए तीर्थयात्रियों को आश्वस्त करने और ज़मीनी हालात की जानकारी देने के लिए कदम बढ़ाया। भाजपा विधायक जनक राज ने बताया कि लगभग 15,000 तीर्थयात्री भरमौर और आसपास के मार्गों से पैदल अपने घर वापसी की यात्रा शुरू कर चुके हैं।

उन्होंने कहा अभी तक आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 11 बताई गई है। आने वाले दिनों में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन शुक्र है कि इससे ज्यादा किसी बड़ी जान – माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

डॉ. जनक राज ने बताया कि हर साल तीर्थयात्रा के दौरान दुर्गम रास्तों के कारण लगभग 20 – 25 श्रद्धालु घायल हो जाते हैं, लेकिन इस साल प्राकृतिक आपदा के कारण यात्रा और भी कठिन हो गई है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार आपदा के समय गंभीर नहीं है, जहां सरकार धरातल पर फेल हो चुकी है वहीं सरकार के आलाकमान अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है कि चंबा जिला है में किस प्रकार की तकलीफ जनता को हो रही है। जनता स्वयं ही जनता की मदद कर रही है पर प्रशासन की मदद लगभग लगभग ज़ीरो है।

उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन धरातल पर काम कर रहा है एक – एक व्यक्ति की मदद कर रहा है और चंबा जिला में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और भाजपा के लोग लगातार जनता के बीच है। जिस परिवार को राशन उपलब्ध कराना है उसको राशन दिया जा रहा है और जिस परिवार को अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा, व्यवस्था एवं वस्तु की जरूरत है उसको भी जरूरत अनुसार दी जा रही है।

केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने 77 वें स्थापना दिवस समारोह पर 27 उत्कृष्ट कृषकों का सम्मानित किया

शिमला / शैल। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ने 27 अगस्त को अपना 77 वां स्थापना दिवस मनाया।

इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के उपनिदेशक डॉ. संजय कुमार सिंह, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। शिमला नगर निगम के मेयर सुरेन्द्र चौहान एवं डॉ. वी.पी. शर्मा, निदेशक, मशरूम अनुसंधान निदेशालय, सोलन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया।

संस्थान के निदेशक डॉ. ब्रजेश सिंह ने संस्थान के द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला उन्होने बताया की संस्थान ने भारत के प्रत्येक क्षेत्र और जलवायु के लिए आलू की खेती हेतु कुल 76 किस्में विकसित की हैं और 04 नयी किस्मों विकसित कर ली गयी हैं जो की जल्द हीं हितधारकों के लिए सरकार की अधिसूचना के बाद उपलब्ध होगी । उन्होने आलू उत्पादन के भंडारण और प्रसंस्करण हेतु कृषि तकनीकें, आलू आधारित फसल प्रणालियां, संसाधन प्रबंधन और फसल सुरक्षा के लिए तकनीकों की जानकारी दी ।

मुख्य अतिथि डॉ संजय सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया कि पहले आलू की किस्में केवल लंबे दिनों और कम तापमान पर ही उग सकती थीं और यह वातावरण केवल ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध था। जिसके कारण मैदानी इलाकों में आलू की खेती संभव नहीं थी। लेकिन केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान के बदौलत, यह फसल भारत के अन्य हिस्सों में भी फैल गई और यह किचन गार्डन से आगे बढ़कर भारतीय रसोई तक पहुँच गयी और आज भारत विश्व के अग्रणी आलू उत्पादक देशों की सूची में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है।

मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि इस तरह का उत्कृष्ट संस्थान न केवल शिमला शहर की पहचान है बल्कि आईसीएआर और विश्व के अव्वल संस्थानों की श्रेणी में आता है।

इस अवसर पर संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. तनुजा बक्सेठ, तकनीकी वर्ग से श्रीमती कुसुम सिंह, प्रशासनिक वर्ग से गुरुजीत सिंह एवं कुशल सहायक वर्ग से रणवीर सिंह को उनके उत्कृष्ट कार्यों पर संस्थान द्वारा बेस्ट वर्कर पुरस्कार से सम्मानित गया। संस्थान द्वारा राज्य के 27 उत्कृष्ट कृषकों को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। डॉ. आरती बैरवा, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अश्वनी के. शर्मा, प्रभारी, कुफरी फागू इकाई डॉ. संजीव शर्मा, प्रमुख, पादप सुरक्षा डॉ. बृजेश सिंह को प्रशंसा प्रमाण पत्र पीसीएन क्वारंटाइन मुक्त बीज उत्पादन हेतु प्रदान किया गया।

इस दौरान मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के सम्बोधन के अलावा शिमला स्थित स्कूल के बच्चों के ज्ञानवर्धन हेतु संस्थान द्वारा आलू पर किए जा रहे शोध पर प्रकाश डाला गया एवं उन्हें संस्थान की प्रयोगशालाएं दिखाई गई। इस मौके पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थानों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया।

उपायुक्त ने इंदौरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, राहत शिविरों का लिया जायजा

शिमला / शैल। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मौके की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया।

उपायुक्त ने मीलवां पंचायत का भी दौरा किया, जहां उन्होंने लोगों से संवाद किया और उनकी कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय मीलवां में स्थापित राहत शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में ठहरे प्रभावित परिवारों से उन्होंने बातचीत की और खाने – पीने, स्वास्थ्य सुविधा व अन्य आवश्यक प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत शिविरों में किसी प्रकार की कमी न रहने पाये और प्रभावित परिवारों को समय पर भोजन, स्वच्छ पेयजल व स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं।

इसके उपरांत उपायुक्त हेमराज बैरवा ने उपमंडल के सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विधायक मलेंद्र राजन भी उपस्थित रहे, जिनके साथ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और राहत एवं बचाव कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से युद्धस्तर पर कार्य करें ताकि प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत मिल सके।

उन्होंने बताया कि प्रशासन बीबीएमबी के साथ लगातार संपर्क में है और जल स्तर की स्थिति पर पल – पल नजर रखी जा रही है।

उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने अपील की कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा – निर्देशों का पालन करें।

विद्यार्थियों को हिंदी के प्रति जागरूक करेगा केंद्रीय विवि

शिमला / शैल। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी माह के तहत जिला कांगड़ा के सरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिये इस वर्ष कुल 29 प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा। जिसमें विश्वविद्यालय के सभी परिसरों के लिए कुल 25 प्रतियोगिताएं तथा विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए कुल 04 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में स्नातक स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए कांगड़ा जिले के छः महाविद्यालयों और धर्मशाला के तीन विद्यालयों प्राथमिक, मिडल, उच्च और उच्चतर माध्यमिक के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. सत प्रकाश बंसल ने कहा कि हिंदी माह के तहत हमें अपना आत्ममंथन करना होगा और हिंदी के प्रयोग को सभी क्षेत्रों में बढ़ाना होगा। इस बार हिंदी माह के तहत विश्वविद्यालय सामुदायिक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। जिला कांगड़ा के कई सरकारी शिक्षण संस्थानों को प्रतिभागिता के लिए आमंत्रित किया गया है। बच्चों में इसको लेकर काफी उत्साह दिख रहा है। ।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य है कि हमारे बच्चों में, जिनके हाथों में हमारे राष्ट्र का भविष्य है, उनमें अपनी भाषाओं के प्रति प्रेम और सजगता बढ़े। हम सभी हिंदी सहित अपनी सभी राष्ट्रीय भाषाओं पर गर्व करते हुए उसका प्रयोग सभी क्षेत्रों में करें, उन्हें सुदृढ़ करें। विद्यालय के प्रतिभागी बालक – बालिकाओं को प्रतिभागिता प्रमाणपत्र और पांच – पांच विजेताओं को प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। इन प्रतियोगिताओं में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों सहित सभी परिसरों के स्नातक, स्नातकोतर एवं शोद्यार्थियों द्वारा प्रतिभागिता की जाएगी। विश्वविद्यालय का प्रयास है कि हिंदी सहित सभी राष्ट्रीय भाषाओं को शिक्षा – दीक्षा की भाषा बनने के लिए इन्हें सक्षम किया जाये। विवि इसके लिए सभी कर्मियों को शब्दावलियों एवं विभिन्न संसाधनों से लैस किया जा रहा है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

सुक्खू सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर उठे गंभीर सवाल

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर जो चिंता कैग रिपोर्ट में व्यक्त की गयी है उससे भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। बढ़ता कर्ज भार और उसके मुकाबले में घटता राजस्व एक ऐसी स्थिति के प्रति गहरा संकट और संदेश है जिस पर यदि समय रहते अंकुश न लगाया गया तो स्थितियां बहुत भयानक हो जायेंगी। क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक जो कर्ज उठाया जा रहा है उसका 64 % से 70% तक सरकार वेतन, पैन्शन और ब्याज की अदायगी पर खर्च कर रही है और विकासात्मक कार्यो के लिये जिन से राजस्व पैदा होगा सिर्फ 30% ही बचता है। जबकि सरकार जो भी कर्ज लेती है वह विकास कार्यो में निवेश के नाम पर लेती है। क्योंकि प्रतिबद्ध खर्चो के लिए कर्ज उठाने का नियमों में कोई प्रावधान ही नहीं है। प्रतिबद्ध खर्च सरकार को अपने ही संसाधनों से पूरे करने होते हैं और यह संसाधन है ही नहीं। इसके लिये गलत बयानी करके विकास के नाम पर कर्ज उठाया जाता है और इसी से सरकार के वित्तीय प्रबंधन का कौशल सामने आता है। सुक्खू सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तब प्रदेश का कुल कर्जभार 70000 करोड़ के करीब था जो अब बढ़कर एक करोड़ पहुंच गया है। हर माह सरकार को करीब एक हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। चालू वित्त वर्ष में सरकार की कर्ज लेने की सीमा 7000 करोड़ और अभी तक सरकार 6500 करोड़ के करीब कर्ज ले चुकी है। अगले आने वाले समय में कैसे जुगाड़ किया जायेगा यहां एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है।

सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इतना कर्ज उठाकर भी यह सरकार पिछली देनदारियां पूरी नहीं कर पायी है। यह सवाल उठने लग पड़ा है कि आखिर कर्ज का निवेश हो कहां रहा है। सरकार लगातार यह आरोप लगाती आ रही है कि उसे केन्द्र की ओर से पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। जबकि सदन के पटल पर सवालों के जवाब में आये आंकड़ों के अनुसार यह आरोप आधारहीन हो जाता है। क्योंकि आपदा प्रबंधन में ही 31-7-2025 तक तीन वर्षो में 3578 करोड़ 63 लाख सरकार को मिले हैं। एडीबी से चार परियोजनाओं के लिए दो वर्षो में 31-7-2025 तक 625 करोड़ 87 लाख मिले हैं। जल शक्ति विभाग में 1-1-23 से 31-7-2025 तक 1598 करोड़ 76 लाख 22900 रुपए मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग में चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए 1877.24 करोड़ मिले हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में केन्द्र से इतनी धनराशि मिलने के बाद भी आयुष्मान भारत और हिम केयर में 657 करोड़ की देनदारियां पड़ी हुई हैं। कर्मचारियों के मैडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। लेकिन वित्तीय प्रबंधन कमजोर होने के कारण केन्द्र से मिला 1024 करोड़ यह सरकार खर्च नहीं कर पायी और यह पैसा केन्द्र को वापस कर दिया गया। इसी तरह 14 मामलों के लिये 711 करोड़ का अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया और अन्त में यह सामने आया कि इन मामलों के लिये मूल बजट में जो प्रावधान किया गया था वह ही खर्च नहीं हो पाया। इसी तरह 40 परियोजनाओं के लिये जारी किये गये बजट में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया।

संसाधनों के नाम पर सरकार ने दस उपकर लगा रखे हैं पंचायती राज संस्था मार्च 99 से, मोटर वाहन पर सैस 1-4-2017 से, गऊ धन विकास निधि, 1-8-2018, एम्बुलैन्स सेवा फण्ड 1-8-2018 से, कोविड सैस 1-6-2020 से 2023 तक, मिल्क सैस 1-4-2023 से, प्राकृतिक खेती सैस 1-4-2024 से, दुग्ध उपकर 26-9-2024से, मिल्कऔर पर्यावरण सैस 10-09-2009 से, लेबर सैस 4-12-2009 और 2023 से इन उपकरों से अब तक सरकार 762 करोड़ 13 लाख 60421. 90 पैसे कमा चुकी है। यही नहीं सुक्खू सरकार ने ही जो कर और शुल्क लगाये हैं उनसे अब तक 5200 करोड़ अर्जित कर चुकी है। यदि सरकार द्वारा रखे गये तीन वर्षो के बजटों का आकलन किया जाये तो इनमें कुल आय और खर्चे में जो घाटा दिखाया गया है उसके आंकड़े उठाये गये कर्ज से मेल नहीं खाते हैं। अब जब इस वर्ष लिये जाने वाले कुल 7000 करोड़ के कर्ज में अब बचे ही एक हजार से कम है तो अगले महीनों का प्रबंध कैसे होगा? निश्चित है कि आने वाले समय में वेतन और पैन्शन का सुचारु भुगतान कैसे हो पायेगा यह बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्योंकि जनता पर और कर्ज भार बढ़ाना संभव नहीं होगा और राजनीतिक मित्रों को दी गयी ताजपोशियां और आर्थिक लाभों में कटौती नहीं हो पायेगी। इस परिदृश्य में अगला वित्तीय प्रबंधन सरकार के लिए कसौटी हो जायेगा।

भाजपा विधायक दल ने किया नगर निगम संशोधन विधेयक 2025 का विरोध

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2025 खुलेआम संविधान का उल्लंघन है, जिसे सुक्खू सरकार कर रही है। सरकार का यह कृत्य कांग्रेस के असली चरित्र को उजागर करता है। एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश में संविधान की किताब लेकर घूमते हैं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा के अन्दर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (यू) का खुला उल्लंघन है। यह अनुच्छेद नगर निगम के चुनाव 5 साल के भीतर करवाने की व्यवस्था देता है। निकाय भंग होने के 6 महीने के भीतर अनिवार्यत: चुनाव करवाने के लिए निर्देशित करता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार अपनी नाकामियां छुपाने और चुनाव में निश्चित हो चुकी अपनी हार से बचने के लिए संविधान की अवहेलना कर रही है। व्यवस्था परिवर्तन की सरकार द्वारा यह हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है। भाजपा विधायक दल इसका खुला विरोध करती है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बेहद शातिराना ढंग से संस्थानों को बंद कर रही है। एक तरफ सरकार पहले विद्यालयों से शिक्षक हटा दे रही है, शिक्षकों की कमी से छात्र अपना नाम कटवा कर कहीं और चले जा रहे हैं। तब सरकार जीरो एनरोलमेंट का बहाना बनाकर स्कूल को बंद कर दे रही है। लगभग 2000 से ज्यादा संस्थान कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब सरकार बनी और सिर्फ मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की शपथ हुई थी कैबिनेट का गठन भी नहीं हुआ था तब भी दोनों लोगों ने मिलकर धड़ाधड़ संस्थानों को बंद करना शुरू कर दिया था। प्रदेश ने पहली बार देखा कि किस तरह से एक सरकार जिसका काम संस्थान खोलने और लोगों को सुविधा देना है वह धड़ाधड़ चले हुए संस्थानों को बंद कर रही है। सरकार की यह कारवाई सिर्फ राजनीतिक विद्वेष का नतीजा थी।

कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हुआ उद्योगों का पलायन:जयराम

शिमला/शैल। कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार की बजह से राज्य से उद्योगों का पलायन हुआ है जिसे रोकने में मुख्यमंत्री नाकाम साबित हुए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश में नए उद्योग लगाने और उद्योगों के पलायन को लेकर सवाल पूछा था लेकिन उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से जो जवाब दिया गया।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आयी है, तब से या तो उद्योग बंद हो रहे हैं या फिर प्रदेश से पलायन कर रहे हैं। उद्योगों का हिमाचल की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है और रोजगार देने में भी योगदान है लेकिन यह सरकार उद्योगों को परेशान करने का काम कर रही है। सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। उद्योगों से उगाही की जा रही है, जिसके चलते यहां से उद्योग पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण राज्य से उद्योग लगातार पलायन कर रहे हैं और बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ रही है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार के समय राज्य को मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क जैसी बड़ी परियोजनाएं मिली थीं, लेकिन मौजूदा सरकार उद्योग बचाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है।

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पिछले तीन वर्षो में प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हुआ। जबकि हमारे कार्यकाल में धर्मशाला में इंवेस्टर मीट हुई जिसमें 703 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के ज़रिए 96 हज़ार 721 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति बनी। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 13 हज़ार 488 करोड़ की 236 परियोजनाएं हुई। जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 28 हज़ार 197 करोड़ रुपये की 287 परियोजनाएं ज़मीन पर उतरी थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं शामिल हुए थे। हमने उद्योगों से हजारों बेरोजगारों को रोजगार दिया था जबकि यहां उद्योगपति डराकर बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है।